

योजना मंत्रालय

मांग संख्या 65

योजना मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003		
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		61.02	30.50	91.52	58.17	29.30	87.47	15.71	30.43	46.14
पूंजी		15.00	...	15.00	5.00	...	5.00	7.50	...	7.50
जोड़		76.02	30.50	106.52	63.17	29.30	92.47	23.21	30.43	53.64
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	0.39	0.39	...	0.26	0.26	...	0.38	0.38
2. योजना आयोग	3451	54.48	26.11	80.59	53.90	25.24	79.14	5.13	26.45	31.58
3. राज्य मानव विकास रिपोर्ट के लिए यूएनडीपी सहायता	3475	0.66	...	0.66	0.53	...	0.53	0.65	...	0.65
	3601	0.17	...	0.17	0.17	...	0.17	0.17	...	0.17
	जोड़	0.83	...	0.83	0.70	...	0.70	0.82	...	0.82
4. जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के देश स्तरीय आकलन के लिए डब्ल्यू.एच.ओ. सहायता	2215	0.06	...	0.06
5. अन्य	3475	5.71	4.00	9.71	3.57	3.80	7.37	9.70	3.60	13.30
	5475	15.00	...	15.00	5.00	...	5.00	7.50	...	7.50
	जोड़	20.71	4.00	24.71	8.57	3.80	12.37	17.20	3.60	20.80
कुल जोड़		76.02	30.50	106.52	63.17	29.30	92.47	23.21	30.43	53.64
ख आयोजना परिचय*:-	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आ.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आ.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आ.ब. बा.सं.	जोड़
1. सचिवालय आर्थिक सेवा	13451	54.48	...	54.48	53.90	...	53.90	5.13	...	5.13
2. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	21.54	...	21.54	9.27	...	9.27	18.08	...	18.08
जोड़		76.02	...	76.02	63.17	...	63.17	23.21	...	23.21

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** इसमें योजना मंत्री और योजना राज्य मंत्री के सचिवालय के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2. **योजना आयोग/योजना बोर्ड:** इस मद में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) सहित योजना आयोग के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

3. इसमें राज्य मानव संसाधन विकास रिपोर्टों की तैयारी के लिए यू.एन.डी.पी. सहायता का प्रावधान किया गया है।

4. **विश्व स्वास्थ्य संगठन सहायता योजना:** इस योजना का उद्देश्य जलापूर्ति तथा स्वच्छता का देश स्तरीय मूल्यांकन करना है। योजना आयोग ने जलापूर्ति तथा स्वच्छता का देश स्तरीय मूल्यांकन करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहायता का कुल मूल्य 0.60 करोड़ रुपए है। यह परियोजना जून, 2002 तक समाप्त होनी है।

5. **अन्य:** (क) अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आईएएमआर), को सहायता अनुदान, जो भारत में मानव संसाधनों के स्वरूप, विशेषता तथा उपयोग संबंधी जानकारी की प्रगति के लिए तथा सरकारी विभागों को जनशक्ति अनुसंधान सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है, (ख) विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं को प्रशिक्षण, अनुसंधान और संस्थाओं के विकास इत्यादि के लिए सहायता अनुदान, (ग) 'व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान' योजना के अंतर्गत भुगतान (घ) कार्यालय पद्धति का आधुनिकीकरण; (ङ) राष्ट्र विकास को प्रतिबिम्बित करने वाले सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक व्यापक आंकड़ा बैंक का निर्माण करने तथा राज्य विकास रिपोर्टों इत्यादि तैयार करने के लिए आयोजना हेतु 50वें वर्ष की पहल; (च) जनसंख्या संबंधी आयोग के लिए अनुदान सहायता प्रदान करना जिसे सरकार द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जनसंख्या संबंधी राष्ट्रीय आयोग के गठन के परिणामस्वरूप संशोधित अनुमान 2001-02 स्तर पर शुरू किया गया है।